# सभी विभागों के निवेश प्रस्तावों की निगरानी करेगा इन्वेस्ट यूपी

## एनओसी से लेकर भूमि आवंटन तक में निवेशकों की करेगा मदद

**राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ:** इन्वेस्ट यूपी अब विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित निवेश प्रस्तावों की निगरानी करेगा। साथ ही, निवेशकों को एनओसी दिलाने से लेकर विभागों से जुड़े अन्य मामलों में भी मदद करेगा। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी ने सभी सरकारी विभागों से संबंधित निवेश प्रस्तावों की जानकारी एकत्र करनी शुरू कर दी है। वर्तमान में निवेश सारथी पोर्टल पर पंजीकृत 43 सरकारी विभागों से संबंधित निवेश प्रस्तावों को इन्वेस्ट यूपी अपने माध्यम से आगे भेजने की तैयारी कर रहा है।

भ्रष्टाचार के आरोप में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश के निलंबन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों की समस्याओं को हल कराने के लिए इन्वेस्ट यूपी की कार्यप्रणाली में सुधार व पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद इन्वेस्ट यूपी ने सभी सरकारी विभागों की योजनाओं की जानकारी एकत्र करनी शुरू कर दी है।

साथ ही निवेश से संबंधित योजनाओं को लेकर कितना निवेश आया है और कितने एमओयू पर

### निवेश सारथी पोर्टल पर पंजीकृत 43 विभागों की परियोजनाओं पर इन्वेस्ट यूपी की नजर

हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, इसकी भी जानकारी एकत्र की गई है।

इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत, अवस्थापना विकास, आबकारी, आवास, उच्च शिक्षा, उद्यान, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, कृषि, खादी एवं ग्रामोद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, दुग्ध विकास, नगर विकास, निजी पूंजी निवेश, पर्यटन, पशुधन, मत्स्य, रेशम, व्यवसायिक शिक्षा, वस्त्रोद्योग, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, शिक्षा, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता व सार्वजनिक उद्यम विभागों के माध्यम से चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इन्वेस्ट यूपी ने एकत्र की है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए यह कोशिश है कि सभी सरकारी विभागों से संबंधित निवेश परियोजनाओं की निगरानी इन्वेस्ट यूपी के जरिये की जाए।

### पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे ई-वे हब

पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर राहगीरों के लिए ई-वे हब का निर्माण किया जाएगा। उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की कार्ययोजना के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चार और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आठ ई-वे हब बनाए जाएंगे। इन ई-वे हब में पेट्रोल व सीएनजी पंप, ईवी चार्जिंग सेंटर, व्यापारिक स्थल, पेयजल व शौचालय, फूडकोर्ट, होटल, थीमपार्क, लाजिस्टिक्स, बच्चों के खेलने के स्थल सहित अन्य गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई यूपीडा की बैठक में ई-वे हब विकसित करने का खाका खींचा गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 81.89 हेक्टेयर क्षेत्र में ई-वे हब का निर्माण किया जाएगा। बाराबंकी में एक्सप्रेसवे के बायीं तरफ 10 हेक्टेयर में, अमेठी में एक्सप्रेसवे के दाहिनी ओर 10.12 हेक्टेयर में क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब का निर्माण किया जाएगा।